

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :-39/2008

डॉ. कैलाश गुप्ता

—अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, पशुपालन विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, पशुपालन विभाग, राजस्थान, टोंक रोड़, जयपुर, राज.।
3. सहायक निदेशक, पशुपालन विभाग, वेटनरी पोली-क्लीनिक, बांसवाड़ा, राज.।

—प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 11.08.2023

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : कोई उपस्थित नहीं।

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री पुष्पेन्द्र पाल सिंह, अति. राजकीय अधिवक्ता।

समक्ष :- अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. प्रस्तुत पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने यह तथ्य अंकित किये हैं कि आदेश दिनांक 14.06.2002 (अनुलग्नक-1) के द्वारा अपीलार्थी, जो पशु चिकित्सा अधिकारी पद पर कार्यरत था, उसे वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी के पद के विपरीत स्वयं के वेतनमान में पदस्थापित किया गया। अपीलार्थी ने वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी के पद का कार्यग्रहण किया, परंतु अपीलार्थी को वेतन पशु चिकित्सा अधिकारी के पद का ही प्रदान किया गया। बाद में आदेश दिनांक 25.01.2006 के द्वारा अपीलार्थी को वर्ष 1999-2000 की रिक्तियों के विरुद्ध वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई। इस प्रकार अपीलार्थी को वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थापन करने से पहले ही रिक्ति वर्ष 1999-2000 से ही वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदोन्नति दी गई। ऐसे में अपीलार्थी ने वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी के रूप में दिनांक 14.06.2002 के अनुसरण में दिया है, उस पर अपीलार्थी पातेय वेतन के स्थान पर वास्तविक वेतन वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी के पद का ही प्राप्त करने का अधिकारी है।
2. प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जवाब प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलार्थी का आदेश दिनांक 14-6-2002 द्वारा पदस्थापन स्वयं के वेतनमान में किया गया है। उक्त आदेश में यह स्पष्ट शर्त है कि इस आदेश द्वारा पदस्थापित अधिकारी उच्च वेतनमान अथवा पदोन्नति के पात्र नहीं होंगे। सेवा नियमों के अनुसार इनका उक्त आदेशानुसार उच्च पद के विपरीत कार्यग्रहण किया जाना बाध्यकारी नहीं था। विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा पर अपीलार्थी का

चयन वर्ष 1999–2000 की रिक्तियों के विरुद्ध होने पर आदेश दिनांक 25-1-2006 द्वारा पदोन्नत किया गया है। अतः अपीलार्थी को दिनांक 31-3-2000 से काल्पनिक लाभ देते हुए पदोन्नति पर वास्तविक कार्यग्रहण दिनांक 8-2-2006 से नकद लाभ सही दिया गया है।

3. हमनें दोनों पक्षों द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया। माननीय उच्च न्यायालय ने प्रकरण शिव कुमार गुप्ता बनाम राजस्थान राज्य एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 9744/2015 में आदेश दिनांक 07.09.2015 में निम्न प्रकार से मत व्यक्त किया गया है:—

"It is submitted that posting of the petitioners as Lecturer was made as an administrative arrangement on temporary basis in their pantey vetan. The term pantey vetan as explained by learned Government Advocate is the pay-scale in which the petitioners were already running at the time of their posting as Lecturer. The fact mentioned in the reply that the petitioners are working as Lecturer is sufficient to establish that adequate number of vacancies pertaining to the post of Lecturer were available and the respondents utilised services of the petitioners thereon without making promotions in accordance with the Rules. When the respondents are utilizing services of the petitioners on the post of Lecturer that too from last about a decade, then there is no just reason available to deny pay-scale pertaining to the post concern. The posting of the petitioners on higher post, as a matter of fact, is nothing but a promotion looking to the administrative exigency, though that is termed as administration arrangement in pantey vetan. Once the services of the petitioners are utilized on higher post, they became entitled for fixation of their pay in the pay-scale attached with that post. They are discharging the same duties as discharged by other lecturers employed by way of direct recruitment or by way of promotion, as such the respondents are required to maintain a parity in granting pay to the persons discharging similar duties. The case of the petitioners is not of intermittent officiation on higher post while discharging their normal duties but of discharging duties of higher post for all purposes excluding the duties relating to the substantive post held by them. The non grant of the pay-scale applicable to the post of Lecturer to the petitioners despite utilizing their services on that post is not permissible in view of the doctrine of equal pay for equal work enshrined under [Article 39\(d\)](#) read with [Article 14](#) of the Constitution of India.

Accordingly, this petition for writ is allowed. The respondents are directed to make fixation of the petitioners' pay in the pay-scale

pertaining to the post of Lecturer from the date they were posted on the post aforesaid under the orders (Annex.1) collectively. The necessary fixation in pursuant to the directions aforesaid is required to be made within a period of three months from today. The petitioners shall also be entitled for arrears of wages. "

4. उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत से स्पष्ट है कि अपीलार्थी ने जो सेवा दिनांक 14.06.2002 के आदेश के अनुसरण में वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी के रूप में दी है और अपीलार्थी की पदोन्नति इससे पूर्व की रिक्ति के वर्ष से है। अपीलार्थी की नियुक्ति वरिष्ठ पुश चिकित्सा अधिकारी के पद पर हो चुकी है तो अपीलार्थी वरिष्ठ पुश चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थापित होने की दिनांक से वरिष्ठ पुश चिकित्सा अधिकारी के पद का वास्तविक वेतन प्राप्त करने का अधिकारी है।
5. अतः अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलार्थी को वरिष्ठ पुश चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्यग्रहण करने की दिनांक से वरिष्ठ पुश चिकित्सा अधिकारी के पद का वास्तविक वेतन का लाभ व पारिणामिक लाभ प्रदान किये जावे।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)